

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(भिन्गयी गोपाल, आर्डी०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

74 / 2020  
19-11-2020

भरतलाल पुत्र रामफूल गीणा निवासी ग्राम-अलीपुरा भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला  
टोंक राज०

-अपीलान्ट

वनाम

तहसीलदार उनियारा जिला- टोंक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार उनियारा दिनांक 29-10-2020 मिसल नम्बर 1277 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 29-10-2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 105, 97/640 वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा में अतिक्रमण कर मकान, जोत व उडद की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 105/रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की वहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने वहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया ओर पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जाँच किये एवं अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विधान एवं तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई ओर बिना



f

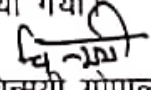
मौके पर जाकर स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये ही निर्णय पारित कर दिया जबकि विधि अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं ? कब्जा साबित होने पर ही निर्णय पारित किया जाता, उक्त निर्णय गलत साबित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट का मकान सरकारी भूमि पर नहीं है स्वयं की आराजी पर मकान का निर्माण है। अपीलान्ट के पिताजी के समय से लगभग 25-30 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला हा रहा है, जो कि खसरा परिवर्तनशील से भी साबित है। इस कारण उक्त एडवर्स प्रजेशन के आधार पर भी अपीलान्ट के विरुद्ध कोई धारा-91 की कार्यवाही मेन्टेनेवल नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहसीलदार उनियारा ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन राजाएँ क्रमशः भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावारा की राजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी राजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। विवादित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 105, 97/640 वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा में अतिक्रमण कर मकान, जोत व उडद की फसल काश्त की है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्टीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 105, 97/640 वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा में अतिक्रमण कर मकान, जोत व उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में स्वयं ने माना है कि अपीलान्ट के पिताजी के समय से लगभग 25-30 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला हा रहा है, जो कि खसरा परिवर्तनशील से भी साबित है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 29-10-2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोक